

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 278 / 2002 / जयपुर.

मैसर्स रियूनियन इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा० लिमिटेड,
C/o वर्मा एण्ड एसोसियेट्स,
बी-5, नंदप्लाजा, गीजगढ़ हाऊस, हवा सड़क, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़, सिरौही.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

कोई नहीं

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

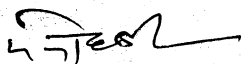
निर्णय दिनांक : 15 / 12 / 2014

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 469/आरएसटी/जेपीआर/बी/99-2000 में पारित किये गये आदेश दिनांक 02.01.2001 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़ (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 78(5) के तहत के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 12.04.99 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 10.04.99 को वाहन संख्या आर.जे.19/जी-4793 को चैक किये जाने पर वाहन में 'इलेक्ट्रिक केबल' मुम्बई से जोधपुर के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित घोषणा-पत्र एस.टी.18ए प्रस्तुत किया गया, जो उक्त जांच पूर्णतया रिक्त पाया गया। इस पर सक्षम अधिकारी ने माल परिवहन में अधिनियम की धारा 78(2) सपिटल राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति रुपये 1,69,728/- का आरोपण आदेश दिनांक 12.04.99 से किया।

3. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 02.01.2001 से अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 278/2002/जयपुर प्रस्तुत की गयी। इस पर राजस्थान कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ के आदेश दिनांक 07.08.2003 से अपील



लगातार.....2

स्वीकार की जाकर सक्षम अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश अपास्त किये गये। माननीय एकलपीठ के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी राजस्व द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 545/2005 प्रस्तुत की गयी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.01.2014 से उक्त निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण कर बोर्ड को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) एस.सी.सी. 269 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी; (2009) 1 एस.सी.सी. 309 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम बजाज इलेक्ट्रिकल्स एवं (2002) 1 एस.सी.सी. 279 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम डी. पी. मेटल्स के प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में पुनः निर्णय पारित किया जावे। माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 15.01.2014 निम्नानुसार है :—

"Learned counsel for the parties submit that the instant revision stands squarely covered by the order dated 22.1.2010 passed by this Court in S.B. Sales Tax Revision Petition No. 111/2008. It is submitted that the controversy involved in the present case is in relation to the question as to whether penalty under Section 78(5) of the Rajasthan Sales Tax Act could be imposed because the declaration in form No. ST 18A was found to be blank at the time of checking of goods in transit.

This Court following the decisions of the Hon'ble Supreme Court in M/s Guljag Industries vs. CTO (2007) 7 SCC 269, C.T.O. vs. Bajaj Electricals (2009) 1 SCC 309 and State of Rajasthan vs. D.P. Metals (2002) 1 SCC 279, remanded the matter back to the Tax Board to be decided denovo in the light of the aforesaid decisions.

Consequently, the instant revision petition is allowed and the order dated 7.8.2003 passed by the Tax Board, Ajmer is set aside and the matter is remanded back to the Tax Board for deciding the matter afresh in accordance with law after providing opportunity of hearing to the parties."

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों के अनुसरण में प्रकरण में पुनः सुनवाई की जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा रहा है।

5. बावजूद सूचना अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, किन्तु अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री गजानन्द वर्मा द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई है, जिसमें कथन किया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी के अभिभाषक अन्य अपील कार्यों में व्यस्त होने के कारण सुनवाई तिथि को उपस्थित होने में असमर्थ हैं तथा उनके द्वारा लिखित Submission को स्वीकार

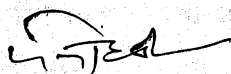


करने की प्रार्थना करते हुए अपील को निर्णीत कर दिये जाने का उल्लेख किया। लिखित बहस में निम्न कथन किये गये हैं :-

(i) उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर का आदेश अविधिक है तथा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के विपरीत है। उपायुक्त (अपील्स) ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल रखा है, जिसमें उन्होंने राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 53 को Consider नहीं किया है। नियम 53 के तहत घोषणा-पत्र एस.टी.18ए केवल कर योग्य माल के परिवहनित किये जाने पर ही लागू होता है। संकर्म संविदाओं के मामलों में जहां करमुक्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है तथा करमुक्ति शुल्क संविदा के सकल मूल्य पर प्रभार्य होता है, तब ऐसे माल पर संकर्म संविदा में प्रयोग किये जाने पर आगे कोई कर लागू नहीं होता है। संकर्म संविदा में प्रयुक्त किये जाने वाले माल पर कोई कर उद्ग्रहणीय नहीं होता है। इस मान्यता के आधार पर आगे उल्लेख किया कि जिस माल को संकर्म संविदा के क्रियान्वयन में प्रयुक्त किया जाये, वह माल करमुक्त माल है तथा उस माल पर घोषणा-पत्र एस.टी. 18ए परिवहन के दौरान साथ में रखना आवश्यकता नहीं है, जबकि विद्वान उपायुक्त (अपील्स) ने इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए शास्ति आरोपण के आदेश को बहाल रखा है।

(ii) विद्वान उपायुक्त (अपील्स) ने अधिनियम की धारा 78(5) में आरोपित शास्ति रुपये 1,69,728/- को बहाल रखने में त्रुटि की है। संकर्म संविदा के क्रियान्वयन में प्रयुक्त माल वाणिज्यिक कर अधिकारी, संकर्म संविदा व पट्टा कर, जोन-द्वितीय, जयपुर के द्वारा जारी मुक्ति प्रमाण-पत्र से आच्छादित था तथा ऐसा माल करमुक्त होने के कारण उस पर आगे राज्य में कोई कर दायित्व नहीं होता है तथा ऐसे माल पर कोई शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। उल्लेखित करमुक्ति प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की है, जो एनेक्श्चर-‘डी’ पर है, जो वाणिज्यिक कर अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ है। यह कर मुक्ति प्रमाण-पत्र बुक नं0 2 सीरियल नं0 2/20 जारी किया हुआ है, जो अधिसूचना क्रमांक एफ.4(11)एफडी गुप-IV/95-75 दिनांक 27.03.1995 के अधीन जारी किया गया है।

(iii) विद्वान उपायुक्त (अपील्स) ने शास्ति आदेश को बहाल रखने में कानूनी भूल की है, आरोपित शास्ति अविधिक, अनुचित व अनौचित्यपूर्ण थी, क्योंकि माल के ऊपर कोई कर दायित्व नहीं था तथा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 53 के तहत घोषणा-पत्र एस.टी.18ए की आवश्यकता नहीं थी।



(iv, v, vi) शास्ति आरोपण तथ्यों को पूर्णतया नजरअंदाज करते हुए आरोपित की है। माल के करमुक्त होने का प्रमाण प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त भी धारा 78(5) में शास्ति आरोपित की है। इसमें नियम 53 के अधीन प्रपत्र एस.टी.18ए लागू नहीं होता है तथा उसे संलग्न करने की आवश्यकता नहीं थी।

(vii, viii, ix) राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 53 केवल संचलन के दौरान कर योग्य माल को परिवहनित किये जाने पर ही लागू होता है तथा तब ही घोषणा-पत्र एस.टी.18ए संलग्न करना आवश्यक है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो माल मुम्बई से राजस्थान परिवहनित किया जा रहा था, वह माल संकर्म संविदा के क्रियान्वयन में काम में लिया जाने वाला माल था। अपीलार्थी व्यवहारी संकर्म संविदा का करमुक्त प्रमाण-पत्र धारक व्यवहारी था तथा संचलन में परिवहनित माल करमुक्त माल होने के कारण राजस्थान में उस पर कोई कर दायित्व नहीं था तथा नियम 53 लागू नहीं होने के कारण प्रपत्र एस.टी.18ए संलग्न करने की आवश्यकता नहीं थी।

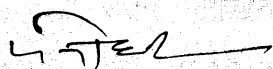
6. विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये हैं :-

- (i) मैसर्स ओरियन्ट सोप कम्पनी जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, ए.सी. वृत्त-द्वितीय, जयपुर
- (ii) मैसर्स इलेक्ट्रिकल केबल इण्डस्ट्रीज बनाम सहायक आयुक्त (ए.ई.)
- (iii) मैसर्स जितेन्द्र एण्ड कम्पनी (आर.एल.डब्ल्यू 2000 (4) राज. 69)
- (iv) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम आयशर लिमिटेड अलवर दिनांक 31.03.2011

7. अग्रिम कथन किया गया कि जांच के समय अपीलार्थी द्वारा फ्रेश बिल, जिसमें 10 प्रतिशत सी.एस.टी. चार्ज किया हुआ था, को लिखित उत्तर के साथ प्रस्तुत कर दिया, उसके उपरान्त भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किया गया।

8. उक्त लिखित बहस में प्रस्तुत तर्कों के साथ में अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की।

9. दौरान बहस प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा उपस्थित हुए। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त परिवहन वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ संलग्न घोषणा-पत्र एस.टी.18ए पूर्णतया रिक्त पाया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) एस.सी.सी. 269 मैसर्स गुलजग



लगातार.....5

इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी में यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि घोषणा-पत्र एस.टी.18ए रिक्त/अपूर्ण पाये जाने पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपणीय है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति पूर्णतया विधिसम्मत है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

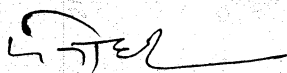
10. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी की लिखित बहस का अवलोकन किया गया। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

11. यह प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.01.2014 द्वारा प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) एस.सी.सी. 269 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी; (2009) 1 एस.सी.सी. 309 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम बजाज इलेक्ट्रिकल्स एवं (2002) 1 एस.सी.सी. 279 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम डी. पी. मैटल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में पुनः निर्णय पारित किया जावे।

12. प्रकरण में उपलब्ध तथ्यानुसार दिनांक 10.04.99 को वाहन संख्या आर. जे.19/जी-4793 को चैक किये जाने पर व्यवहारी के द्वारा कार्य संविदा निष्पादन में उपयोग हेतु अधिसूचित माल बिजली की केबल खाली व अपूर्ण घोषणा-पत्र एस.टी.18ए से वहनित की जा रही थी।

13. प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित दिशा-निर्देशों के अनुसरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) एस.सी.सी. 269 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी का ससम्मान अवलोकन किया गया, जिसमें निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

20. The facts enumerated above in Civil Appeal No.5197 of 2005 is the lead case in which one finds that the goods in movement were carried with blank declaration forms though signed by the consignee. The material particulars like quality, weight and description of the goods required to be filled in by the assessee (consignee) were left blank. Therefore, in this batch of civil appeals we are concerned with

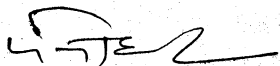


cases where the goods in movement were carried with blank Form ST 18A. In our view, on the face of it there was contravention of Section 78(2) of the RST Act 1994. Under Rule 53 of the RST Rules 1995 (Rule 25C of the RST Rules 1955) every registered dealer who imports taxable goods, for sale within the State, is required to furnish declaration Form 18A completely filled in, in all respects (emphasis supplied by us). Under Rule 53 of the said Rules the counterfoils of the declaration has to be retained by such consignee and its portions marked as 'original' and 'duplicate' have to be carried with the goods in movement. Under Rule 53(1)(c) the driver of the goods in movement has to carry with him documents specified in Section 78(2)(a) as also the declaration form prescribed in Section 78(2)(a). Under the said Rule 53(1)(c) the driver is required to produce the declaration form, suo motu at the check-post at the time of inspection when the competent officer is required to retain the original of the declaration form and return the duplicate portion to the driver. The competent officer shall thereafter forward the original portion of the declaration to the A.O. of the registered dealer or to the authority which has issued the declaration form to the consignee. Under Rule 53(2) the registered dealer is required to submit a statement of import of goods in the Form 18A to the A.O. every quarter. Under Rule 53(4) where a registered dealer fails to furnish such statement the A.O. or the authority who issued the declaration forms may impose penalty under Section 68 of the said Act. Similarly, under Rule 54 of the RST Rules 1994, a dealer who despatches any taxable goods to a place outside the State is also required to carry declaration in Form 18C with the goods in movement for export out of Rajasthan or in the course of interstate trade or commerce. The dealer is also required to submit his

वाच्यता—यत्र ९९.८.१८९ से परागता यत्र जा रहा था।

A are true to his knowledge. In the present case, the entire form was left blank though it had been signed by the consignee. Therefore, the declaration given by the consignee is meaningless. There are no facts given in Part-A. There is no identity of the goods transported. There is no description of the goods in movement. As stated above, the original has to be placed before the A.O. by the officer at the check-post. If the form which ultimately goes to the A.O. is blank in all material respects then it is impossible for the A.O. to assess the dealer and it is this practice which has resulted in loss of revenue in crores to the State. Without description of the goods imported, it is easy to manipulate the value. If material particulars are not submitted, one fails to understand how assessment could be finalized. Moreover, as submitted on behalf of the State it has become a common practice to circulate the same form again and again resulting in loss of revenue to the State. It is for this reason that Rule 53 of the RST Rules 1995 contemplates the form to be submitted duly filled in and duly completed. In the present case, the goods in movement were not supported by duly filled in Form No.18A/18C. Therefore, there was contravention of Section 78(2) of the RST Act 1994.

25. In our view, the aforestated judgment in the case of D.P. Metals (supra) has no application to the present case. We are not concerned in the present case with false or forged documents/declaration. In the present case the goods in movement were carried with the blank declaration Form 18A/18C which was duly signed by the assessee. Therefore, as stated above, we hold that the goods in movement were carried without the declaration Form 18A/18C. Therefore, Section 78(2)(a) stood attracted. Moreover, in the present case, there were no special circumstances indicated by the assessee as to why the forms which were duly signed were not filled in. Therefore, in our view the above judgment in the case of D.P. Metals (supra) has no application to the facts of the present case. As stated, we are concerned with the blank declaration Form 18A/18C which has travelled with the goods in movement, though signed, was left deliberately blank. The declaration Form 18A/18C is like a return under the Income-Tax Act, 1961. The Assessing Officer completes the assessment on the basis of Form 18A/18C. If that form is left blank in all material respects then it is impossible for the A.O. to arrive at the taxable turnover of the assessee. Therefore, in our view, the judgment of this Court in D.P. Metals (supra) has no application to the present case.



26. Before concluding, we may mention that in this batch of civil appeals we have civil appeals filed by the Department. These civil appeals relate to cases where specified documents did not accompanied the goods in movement. The lead case in that regard is Civil Appeal No.5240 of 2005 /026 Assistant Commercial Taxes Officer v. M/s. Guljag Industries Ltd. filed by the Department. We make it clear that our judgment is basically confined to cases where blank/incomplete Form 18A/18C had accompanied the goods in movement. Whatever we have stated above is in the context of the incomplete Form 18A/18C travelling along with the goods in movement. However, Civil Appeal No.5240 of 2005 and such other civil appeals filed by the State (Department) are those cases where the documents were not accompanied the goods in movement, like, the bills of sale, bills of transport etc. In Civil Appeal No.5240 of 2005 the facts of which have been reproduced hereinabove, show that the case was confined to documents not accompanying the goods in movement. Therefore, the said appeals stand on a different footing. They have nothing to do with incomplete forms travelling along with the goods in movement. These civil appeals filed by the State (Department) shall be decided in the light of the judgment of this Court in D.P. Metals (supra). However, cases where goods in movement were accompanied by Form No.18A/18C without duly signed but incomplete in material particulars like description of goods shall be governed by the law discussed hereinabove by us.

27. For the aforestated reasons, we hold that Section 78(5) of the RST Act 1994 (Section 22A(7) of the RST Act 1954) is the section enacted to provide remedy for loss of revenue and it is not enacted to punish the offender for committing economic offence and, therefore, mens rea is not an essential ingredient for contravention of Section 78(2) of the RST Act 1994. That, the breach of Section 78(2) would attract the levy of penalty under Section 78(5) in cases where the goods in movement have travelled with an incomplete Form No.18A/18C. We accordingly uphold the judgment of the High Court of Rajasthan in Sales Tax Revision No.1023/2002 dated 14.10.03 (which is annexed as page No.1 of the appeal paper book in Civil Appeal No.5197 of 2005 filed by M/s. Guljag Industries v. Commercial Taxes Officer).

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (2009) 1 एस.सी.सी. 309 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम बजाज इलेक्ट्रिकल्स में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-



7. In the case of M/s. Guljag Industries v. Commercial Taxes Officer - (2007) 7 SCC 269, this Court has interpreted Section 78(2) of the 1994 Act and Section 78(5) thereof. In that case a vehicle was checked in which certain goods were being transported from a place in Andhra Pradesh. The goods were accompanied by outward gate pass and invoice which indicated the name of the consignor and the consignee. Along with the said goods Form ST 18A was also found. That form was duly signed, however, it did not indicate the description of the goods transported. Therefore, the A.O. held that there was contravention of the provision of Section 22A(3) of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (for short, "the 1954 Act"). He accordingly issued show cause notice to the appellant under Section 22A(7) to show cause why penalty should not be imposed for violation of Section 22A(3) of the 1954 Act. In that case also the consignee (importer) pleaded mistake in filling the Declaration Form. The consignee (importer) pleaded lack of knowledge of Hindi language. The A.O. rejected the explanation and imposed penalty under Section 22A(7) of the 1954 Act. The consignee (importer) failed before the Appellate Authority. When the matter was pending in second appeal before the Rajasthan Tax Board, the said 1954 Act was replaced by the 1994 Act. The Tax Board held that the burden was on the Department to establish guilty mind (mens rea) on the part of the consignee. Accordingly, the appeal was allowed. Thereafter revision petition was filed by the Department. By the impugned judgment, the High Court held that mens rea was not a sine qua non for levying penalty in case of contravention of Section 22A(3) of the 1954 Act (Section 78(2) of the 1994 Act). Even on facts, High Court held that not filling the Form was a deliberate act which indicated, in any event, an intention of the consignee to evade the tax. Therefore, in that matter, the consignee filed its appeal by special leave in this Court. After examining the scheme of Section 22A(3) of the 1954 Act, Rule 62A of the Rajasthan Sales Tax Rules, 1955 as well as provisions of Section 78(2) and Section 78(5) of the 1994 Act read with Rules 53 and 54 of the Rajasthan Sales Tax Rules, 1995, this Court held inter alia that mens rea was not necessary for liability of penalty under Section 78(5) of the 1994 Act. It was held that transport of goods in movement with the prescribed Declaration Form duly signed but without giving material particulars would automatically attract levy of penalty for breach of Section 78(2) of the 1994 Act. It was further held that even if mens rea constituted an essential ingredient of the offence under Section 78(2) even then the fact of not giving particulars in the Declaration Form duly signed by the consignee per se would amount to evasion



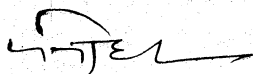
of tax because the modus operandi adopted by the consignee itself indicated mens rea. In that matter heavy reliance was placed by the consignee (appellant) on the judgment of this Court in the case of D.P. Metals (supra). The same judgment is also once again relied upon before us in the present case by the respondent. The judgment in D.P. Metals (supra) has no application. The case of D.P. Metals (supra) was not concerned with blank Declaration Form ST 18A travelling along with the goods in movement. In that matter, the question of interpretation of Section 78(5) did not arise. It was a case in which validity of Section 78(5) was challenged on the ground of it being beyond legislative competence, excessive, arbitrary and unreasonable and therefore violation of Articles 14, 19(1)(a), 301 and 304 of the Constitution.

15. Before concluding, on facts, we may point out that before the A.O. the respondent contended that filling of the Form ST 18A was the responsibility of the transporter and the consignor (which argument presupposes that respondent had not filled the particulars in the Form ST 18A) whereas before the Dy. Commissioner (A) a Form was produced purportedly sent to the consignor which was not accepted. According to the Commissioner (A) it was an afterthought. Before the Tax Board it was submitted by the respondent that a blank Form was sent to the consignor. In view of the above prevarication we hold that the Dy. Commissioner (A) was right in holding that all the above excuses are trotted out as an afterthought. Even the production of the Form before the Dy. Commissioner (A) was an afterthought. Under the 1995 Rules, the consignor is required to give the said Form duly filled in when the consignment is ordered. The consignee has to see that the Form is given to the transporter with the complete details duly filled in by the consignor. If one sees the Form it is clear that it shall be the duty of the consignee or his agent (transporter) to see that the consignor fills the Form. Therefore, on facts we are satisfied that the said Form in ST 18A though signed, remained incomplete. The details required were never supplied. Hence penalty was correctly levied under Section 78(5) of the 1994 Act.

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (2002) 1 एस.सी.सी. 279 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम डी. पी. मेटल्स में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

"Following the decisions of this Court in cases of Sodhi Transport Co. and others (supra), Delite Carriers (supra), Indian Roadways Corporation (supra) Sarna Transport Corporation (supra) and Tripura Goods Transport Association (supra) we hold that the provisions of

लगातार.....11



Section 78(5) of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 are valid and the impugned decision of the High Court in this regard is not correct. These appeals, except Civil Appeal No. 1321 of 2001, are accordingly allowed. Civil Appeal No. 1321 of 2001 is dismissed. Parties to bear their own costs."

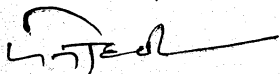
16. इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(11)एफडी गुप-IV/95-75 दिनांक 27.03.1995 निम्न प्रकार है :-

S.O. 425.- In exercise of the powers conferred under S.4(2), RST Act, 1954, the State Govt. hereby exempts from tax the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of Works Contract as mentioned in the List appended to this notfn on the following conditions, namely :-

1. That the contractor claiming exemption holds a valid certificate of exemption with reference to such contract;
2. That such contractor shall pay exemption fee at the rate specified in column 3 of the List appended to this notfn.
3. That the contractor shall not be entitled to use declaration forms to purchase goods at concessional rate of tax or without paying tax for being used in the execution of such contract;
4. that where the contractor uses declaration forms in purchasing any goods in violation of condition No.3, apart from paying exemption fee under this notfn, he shall be liable to pay tax on the said purchases at the rate notified under S.5, with interest thereon. However, if he has paid any tax at the time of such purchases, tax so paid shall be allowed as set-off against the tax payable by him; and
5. That all the provisions of rule 10B, RST Rules, 1955 shall mutatis mutandis apply on such contractors.

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee
1	2	3
1.	Fabrication and installation of Rolling Shutters, Collapsible Gates, Doors, Windows, Frames and Grills, Electrical goods and equipments, Sanitary fittings, Construction or mounting of bodies on Motor Vehicles.	4%
2.	Fabrication and installation of Elevators (Lifts), Air Conditioners and Air Coolers.	6 %

17. इसी प्रकार राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(4)एफडी / टैक्स डिवी./99-126 दिनांक 26.3.1999 द्वारा निर्धारित कर दर से सम्बन्धित प्रविष्टि संख्या 99 निम्न प्रकार है :-



In Exercise of the powers conferred by S.4, RST Act, 1994, and in supersession of this Department notfn. No. F.4(14)FD/Tax Divn/98-16 dated 9.7.1998 (as amended from time to time) [S.No. 1141], the State Govt. hereby provides that with immediate effect the rate of tax payable by a dealer in respect of the goods specified in column 2 of the List annexed hereto, shall be as shown against them in Column 3 of the said List :-

Item No.	Description of goods	Rate of tax (%)
1	2	3
99.	(a) All kinds of electrical goods including electrical fans, desert and room coolers, bulbs and tube lights, wires and cables, electrical home and other appliances, electric earthenware, electrical porcelain ware, insulators and parts and accessories thereof. (b) Electrically operated anti-mosquito devices and repellants used therein, room freshners including those operated electrically or with manual sprayers. (c) Electronic home appliances including parts and accessories thereof.	12

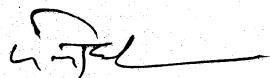
18. इसी प्रकार राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(4)एफडी/टैक्स डिवी./99-157 दिनांक 26.3.1999 द्वारा अधिसूचित घोषित किये गये माल का बिन्दु संख्या 8 निम्न प्रकार है :-

In Exercise of the powers conferred by S.81, RST Act, 1994, and in pursuance of rule 53(1)(a)(i), RST Rules, 1995 and in supersession of this Deptt's notfn. No. F.4(74)FD/Tax Divn/95-43 dated 9.7.1998 (as amended from time to time) [S.No. 1162], the State Govt. hereby notifies the following goods:-

8. All types of electrical goods including UPS and CVTS

19. प्रकरण में आयातित माल बिजली की केबल्स है, जो कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(4)एफडी/टैक्स डिवी./99-126 दिनांक 26.3.1999 के अनुसार 12 प्रतिशत की दर से कर योग्य घोषित की गई है। लिहाजा आयातित माल बिजली की केबल्स कर योग्य है, जिसके परिवहन हेतु राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 53(1)(ए) के अनुसार संचलन के दौरान घोषणा-पत्र एस.टी.18ए संलग्न करना आवश्यक है।

20. आयातित माल 'बिजली की केबल्स' संकर्म संविदा में प्रयोग में लिये जाने के आधार पर उस माल को कर मुक्त माल नहीं कहा जा सकता है। संकर्म संविदा में कर भुगतान के तरीके में भुगतान का एक विकल्प करमुक्ति शुल्क के रूप में भुगतान करना है। संचलन के हस्तगत प्रकरण के तथ्यों में अधिनियम के अधीन कर योग्य माल बिजली के केबल्स राजस्थान विक्रय कर



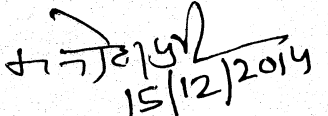
नियम, 1995 के नियम 53 के अधीन अधिसूचित माल है, को रिक्त/अपूर्ण घोषणा-पत्र एस.टी.18ए से आयात किये जाने का तथ्य निर्विवादित है। हस्तगत प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (2007) एस.सी.सी. 269 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, जो पैरा 13 में वर्णित है, में प्रतिपादित सिद्धान्त से पूर्णतया आच्छादित है।

21. इस प्रकार विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व उसमें उल्लेखित न्यायिक दृष्टान्तों को हस्तगत प्रकरण के तथ्यों की समानता के अभाव में लागू नहीं होने के कारण अमान्य व अस्वीकार किया जाता है।

22. प्रस्तुत प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) एस.सी.सी. 269 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के तथ्यों से पूर्णतः आच्छादित होने के कारण अधिनियम के अधीन कर योग्य माल बिजली के केबल्स, जो नियम 53 में अधिसूचित माल है, के संचलन के दौरान खाली घोषणा-पत्र एस.टी.18ए से परिवहनित किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 78(5) में आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि की जाकर कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

23. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

24. निर्णय सुनाया गया।


15/12/2014
(मनोहर पुरी)
सदस्य